

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 566वीं बैठक दिनांक 23/04/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9108/2022 Shri Surendra Saluja, Partner, Barui Bauxite, Laterite, and Ochre Mine Project, Village - Barui, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna, MP Prior Environment Clearance for Bauxite, Laterite, and Ochre Quarry in an area of 5.10 ha. (43079.08 Tonne per annum) (Khasra No. 67/2/k), Village - Barui, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) Env. Consultant: M/s Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP, Gurugram (HR).

This is case of Bauxite, Laterite, and Ochre Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 67/2/k), Village - Barui, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) 5.10 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन) उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खजिन बाकसाइट (लीज एरिया 5.10 हे.) होने के कारण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 125 मीटर एवं दक्षिण दिशा में 180 मीटर की दूरी पर आबादी है। इसी प्रकार 140 मीटर पूर्व दिशा में कच्चा रोड़ है तथा आवंटित क्षेत्र के अंदर कई वृक्ष दिख रहे हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया इस प्रकरण में ओकेजनल ब्लॉस्टिंग प्रस्तावित है जिसका उल्लेख

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

उन्होंने एपेंडिक्स- I के बिंदु क्रमांक-6.4 में किया है। समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र वृक्ष एवं खदान के आसपास काफी हरित क्षेत्र मौजूद है अतः खनन के कारण इको सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 125 मीटर एवं दक्षिण दिशा में 180 मीटर की दूरी पर आबादी है। इसी प्रकार 140 मीटर पूर्व दिशा में कच्चा रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी।
2. टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे।
5. लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम उनकी संख्या, ऊंचाई एवं कालर गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. Study of Eco System Services with special reference to water recharging, wild life value, fauna value and MFP values shall be carried out from a reputed expert agency and same shall be submitted with EIA report.

2. Case No 9107/2022 M/s Madhya Pradesh Mineral Supply Company, Village - Ghatania, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna, MP Prior Environment Clearance for Bauxite, Ochre & White Earth Quarry in an area of 3.845 ha. (20000.39 Tonne per annum) (Khasra No. 10, 11/1-2-3, 12, 15/1), Village - Ghatania, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) Env. Consultant: M/s Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP, Gurugram (HR).

This is case of Bauxite, Ochre & White Earth Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 10, 11/1-2-3, 12, 15/1), Village - Ghatania Udali, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) 3.845 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। चूंकि प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खनिज बाक्साइट (लीज एरिया 3.845 हे.) होने के कारण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रस्तुतीकरण के

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 320 मीटर एवं उत्तर दिशा में 300 मीटर की दूरी पर आबादी है। इसी प्रकार 130 मीटर उत्तर-पूर्व दिशा में कच्चा रोड़ तथा 130 मीटर दक्षिण दिशा में प्राकृतिक नाला है साथ ही आवंटित क्षेत्र के अंदर कई वृक्ष दिख रहे हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया इस प्रकरण में ओकेजनल ब्लॉस्टिंग प्रस्तावित है जिसका उल्लेख उन्होंने एपेंडिक्स- I के बिंदु क्रमांक-6.4 में किया है। समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र वृक्ष एवं खदान के आसपास काफी हरित क्षेत्र मौजूद है अतः खनन के कारण इको सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 320 मीटर एवं उत्तर दिशा में 300 मीटर की दूरी पर आबादी, 130 मीटर उत्तर-पूर्व दिशा में कच्चा रोड़ तथा 130 मीटर दक्षिण दिशा में प्राकृतिक नाला है अतः इनकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी।
2. टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे।
5. लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम उनकी संख्या, ऊंचाई एवं कालर गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
6. Study of Eco System Services with special reference to water recharging, wild life value, fauna value and MFP values shall be carried out from a reputed expert agency and same shall be submitted with EIA report.

3. Case No 9109/2022 Shri Shyam Bansal, Partner, Siddha Kothar Ochre & White Earth, Village- Siddha Kothar, Tehsil- Majhgawan, Dist. Satna, MP Prior Environment Clearance for Bauxite, Laterite, Ochre & White Earth Quarry in an area of 16.187 ha. (43713.044 Tonne per annum) (Khasra No. 97/P), Village - Siddha Kothar, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) Env. Consultant: M/s Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP, Gurugram (HR).

This is case of Bauxite, Laterite, Ochre & White Earth Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 97/P), Village - Siddha Kothar, Bari Amrai, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) 16.187 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

आज दिनांक 23/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। चूंकि प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खजिन बाक्साइट (लीज एरिया 16.187 हे.) होने के कारण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लान में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में तथा दक्षिण दिशा में 25 मीटर पर आबादी है। इसी प्रकार 250 मीटर पर उत्तर-पूर्व दिशा में रोड़ है तथा खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं। खदान क्षेत्र के अंदर पूर्वी भाग से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है जो पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र में स्थित आबादी को पहुँच मार्ग है। अतः राईट ऑफ एक्सेस दिया जाना होगा। इसी प्रकार खदान क्षेत्र के अंदर कुछ मकान / संरचना दिख रही है अतः इनका विवरण तथा यदि आर एण्ड आर प्रस्तावित है तो उसका विवरण ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रकरण में ऑन लाईन उपलब्ध नहीं है, अतः ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया इस प्रकरण में ओकेजनल ब्लॉस्टिंग प्रस्तावित है जिसका उल्लेख उन्होंने एपेंडिक्स- I के बिंदु क्रमांक-6.4 में किया है। समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र वृक्ष एवं खदान के आसपास काफी हरित क्षेत्र मौजूद है अतः खनन के कारण इको सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में तथा दक्षिण दिशा में 25 मीटर पर आबादी है। इसी प्रकार 250 मीटर पर उत्तर-पूर्व दिशा में रोड़ है अतः इनकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी।
2. खदान क्षेत्र के अंदर पूर्वी भाग से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है जो पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र में स्थित आबादी को पहुँच मार्ग है अतः इनकी संरक्षण योजना प्रस्तुत की जानी होगी एवं राईट ऑफ एक्सेस का प्रस्ताव ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये।
3. इसी प्रकार खदान क्षेत्र के अंदर कुछ मकान / संरचना दिख रही है अतः इनका विवरण तथा यदि आर एण्ड आर प्रस्तावित है तो उसका विवरण ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये।
4. टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे।
7. लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं, अतः ट्री इन्वेन्ट्री मय प्रजाति का नाम उनकी संख्या, ऊँचाई एवं कालर गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
8. ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रकरण में ऑन लाईन उपलब्ध नहीं है, अतः ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाये।

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

9. Study of Eco System Services with special reference to water recharging, wild life value, fauna value and MFP values shall be carried out from a reputed expert agency and same shall be submitted with EIA report.

4. Case No 9106/2022 Shri Nishant Jaiswal, Leasee, Mohad Stone Deposit, R/o Bhikangaon, Dist. Khargone, MP -451332 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (5044 cum per annum) (Khasra No. 152/1), Village - Mohad, Tehsil - Jhirniya, Dist. Khargone (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 152/1), Village - Mohad, Tehsil - Jhirniya, Dist. Khargone (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि यह प्रकरण पूर्व आवेदन क्रमांक 8810/2021 के द्वारा सिया से सेक को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भेजा गया था । उक्त प्रकरण को समिति की 531वीं बैठक दिनांक 06/12/21 तथा 545वीं दिनांक 29/01/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई है । सिया की 706वीं बैठक दिनांक 16/02/22 में प्रश्नाधीन खदान के 100 मीटर की दूरी पक्की सड़क होने के कारण न्यूनतम खनन क्षेत्र उपलब्ध नहीं होना परिलक्षित है, के प्रकाश में पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन को निरस्त का निर्णय लिया गया है ।

इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक ने फार्म-2 के सरल क्रमांक-8.1 में एवं पी.एफ.आर में उत्खनन विधि के अंतर्गत रॉक ब्रेकर का उपयोग का उल्लेख करते हुए पुनः आवेदन किया गया, जिसे सिया द्वारा ऑनलाईन परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया गया ।

आज दिनांक 23/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव ऑनलाईन उपस्थित हुए । एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2177 दिनांक 17/09/21 के अनुसार प्रस्तावित खदान से 150 मीटर पर जलीय निकाय है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 75 मीटर पर रोड़ तथा दक्षिण-पूर्वी दिशा में 150 मीटर पर नदी है । इसी प्रकार खदान के पश्चिम दिशा में 170 मीटर तथा पूर्व दिशा में 85 मीटर पर नहर है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि पूर्व की गूगल इमेज 2014-15 से यदि खनन स्थल का अवलोकन किया जाये तो यह ज्ञात होता है कि खनन क्षेत्र को बीच से काटता हुआ एक मौसमी नाला (दक्षिण-पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर) निकल रहा है । समिति ने चर्चा उपरांत यह पाया कि यदि इस नाले से दोनों ओर 50-50 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाये तो खनन हेतु उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा अतः यह प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु अनुशंसा योग्य नहीं है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सिया को अग्रेषित किया जाये ।

5. Case No 9110/2022 M/s Bhopal Municipal Corporation, HFA Cell, 3rd floor, ISBT, Hoshangabad Road, Habibganj, Dist. Bhopal. MP - 462011, Prior Environment Clearance for Construction of Rahul Nagar - Part I (Phase I & Phase II) under PMAY Scheme, On Khasra No. 131 (Part) [Total Area - 28476.00 sqm, Total Built-up Area - 74574.02 sqm] at Village - Rahul Nagar, Kotra Sultanabad, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, (MP) TOR - Voilation M/s. In- situ Enviro Care, Bhopal.

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Rahul Nagar - Part I (Phase I & Phase II) under PMAY Scheme, On Khasra No. 131 (Part) [Total Area - 28476.00 sqm, Total Built-up Area - 74574.02 sqm] at Village - Rahul Nagar, Kotra Sultanabad, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, (MP).

The case was presented by PP Mr. Rajiv Kumar, Head Environment, BMC, Bhopal & their Env. Consultant Shri Ajay Mohan from M/s. In- situ Enviro Care, Bhopal wherein following details of the project were presented:

- The Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) Programme launched by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (MoHUPA), in Mission mode envisions provision of Housing for All.
- Rahul Nagar is a multi unit residential PMAY project which is planned in a plot measuring 28476.00 SQM and located at village Rahul Nagar, Kotra Sultanabaad, Tehsil Huzur, District Bhopal (M.P.).
- We have initiated our Building Construction Project in 2 Phases, Phase I of the project involves the construction of 48 Nos. EWS units, 288 Nos. LIG units. The total maximum height of the project will be 27Mts (P+9) and the Phase II of project involves the construction of 120Nos. 4 BHK HIG units, 120 Nos. 3 BHK HIG units, 1 No. Commercial Block (23 Shops, 60 Offices, 4 Halls) The total maximum height of the project will be 45Mts (B1+B2+P+15)..
- The total land area of the proposed project mentioned as 28476.00 SQM (2.8476 ha) [Phase I - 11276 Sq.Mt. + Phase II - 17200.00 Sq.mt.] and the built-up area as 74574.02 Sq.mt. (Phase I Built up area – 18953.28 Sq.mt. + Phase II Built up area - 55620.74 Sq.mt.)
- As this is a violation case and about 25.41% area of the project has been constructed without getting environment clearance.
- Baseline study period has been proposed summer 2022 as baseline studies is going on.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

• **ENVIRONMENT SENSITIVITY**

Sl. No.	Accessibility	Description	Distance (km)	Direction
1	Highway/ Road/ Kacha Rasta	NH-12	2.8	ENE
2	Railway Stations	Bhopal Railway Station	4.9	NNE
3	Airport	Raja Bhoj Airport	8	NW
4	Hospitals	Sharda Hospital	0.5	SW
		Manisha Hospital	1	SW
5	Institutional Buildings	Demonstration School	1	NW
		School	2.3	NW
6	Post office	Post Office	0.8	NE
7	Densely populated/ Settlements/ Habitat	Bhopal	--	--
8	Water Courses	Halali Nadi	13.6	WNW
		Bara Talab	2.7	NW
		Chhota Talab	2.1	N
		Hatiyakheda Dam	10	WNW
		Mansarovar Talab	2.5	SE
		Anjar Nadi	12.2	ENE
		Patara Nadi	3.4	NNE
		Kaliyasot Nadi	2.7	SSE
		Kerwa Nadi	12.6	SSE

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

		Kaliyasot Dam	2.1	SSE
9	Protected/ Reserved or Sensitive Area	Van Vihar National Park	6.9	WNW
		Bhopal RF	8.7	SW
		Bhopal PF	13.1	SW
10	Seismic Zone	Seismic Zone II.		

During discussion it was observed by the committee that Hon'ble NGT in OA No. 74/2020 (CZ) and & IA 70/2021 had passed a judgement which shall be complied in toto and detailed plan with budgetary allocations for its implementation shall be incorporated in EMP and discussed in length in EIA report.

After deliberation, Committee considering the GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Hence committee recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Status report of constriction took place so far and details of possession given till date shall be incorporated in EIA report.
2. Hon'ble NGT in OA No. 74/2020 (CZ) and & IA 70/2021 had passed a judgement which shall be complied in toto and detailed plan with budgetary allocations for its implementation shall be incorporated in EMP and discussed in length in EIA report.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

3. All the orders passed by Hon'ble NGT or any other Hon'ble Courts in this case shall be discussed in EIA report with their compliance status (for issues related to the environment) till date or activities proposed to be completed in future with time line and budgetary allocations. Complete set of all order copies with their chronology of events shall also be annexed with EIA report.
4. Why project is broken in phases (Phase –I & II) when initially it was sanctioned as one project. Please provide justified reason in EIA report.
5. Any tree uprooting took place during the previous construction? If yes, please provide their details, proper addressal and copy of competent authority's permission for tree uprooting.
6. Any tree uprooting proposed for the remaining construction? If yes, please provide tree inventory with their number, species, collar girth etc with EIA report.
7. Complete drainage plan considering maximum rainfall of the surrounding catchment area shall be discussed in the EIA report to avoid any flooding in future.
8. Proposal for dense plantation (minimum 05 rows) with ground flora, middle floor & top story flora as per NGT orders.
9. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report.
10. Species Plantation and their photographs.
11. Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
12. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
13. Fire NOC to be taken from the concerned department and submitted with EIA.
14. Project description, its importance and the benefits.
15. Under energy conservation plan detail-out solar light erection panels.
16. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage).
17. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
18. Land acquisition status, R & R details (if any).

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

19. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
20. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
21. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
22. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
23. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
24. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area
25. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
26. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
27. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
28. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
29. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

6. Case No 9113/2022 Shri Praveen Chandra Patel, Owner, Bastar Road, Dhamtari, Dist. Dhamtari, Chhattisgarh - 493773, Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 3.140 ha. (38000 MTPA) (Khasra No. 30 (Part), 32 (Part), 33 (Part), 34 (Part), 35 (Part), 36), Village - Bhanwartal, Tehsil - Bicchiya, Dist. Mandla (MP)

This is case of Dolomite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 30 (Part), 32 (Part), 33 (Part), 34 (Part), 35 (Part), 36), Village - Bhanwartal, Tehsil - Bicchiya, Dist. Mandla (MP) 3.140 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1759 दिनांक 23/11/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 25.86 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। खदान के साथ प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र में यह उल्लेखित है कि प्रश्नाधीन खदान स्थल वन क्षेत्र क्रमांक 1236/753 की दूरी 165 मीटर है। उक्त खदान मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय द्वारा वन सीमा से 250 मीटर की दूरी के भीतर स्थित खनि रियायतों के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 07/10/02 के पूर्व दिनांक 02/02/02 को शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसकी कण्डिका-छ में लेख है कि उक्त आदेश पूर्व में स्वीकृत खदानों में लागू नहीं होंगे। किंतु वर्तमान में प्रचलित आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि 2002 के पूर्व स्वीकृत खनिज रियायतों के ऐसे प्रकरण जिनकी वन क्षेत्र से दूरी 250 मीटर से कम है, में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक है या नहीं। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक सम्पूर्ण विवरण औचित्य के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन सिर्फ एक को-आर्डिनेट अपलोड किया गया है जिसके अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर-पूर्व दिशा में 400 मीटर पर तालाब है तथा पश्चिम दिशा में 390 मीटर पर नदी है। ऑनलाईन अपलोड एक को-आर्डिनेट के आधार पर लीज क्षेत्र खुदा हुआ है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के पत्र दिनांक 24/10/19 के अनुसार खदान वर्ष 2012 तक उत्पादनरत रही तथा लगभग 10, 758 मै.टन उत्पादन किया गया है।

यदि माइन प्लान में उल्लेखित को-आर्डिनेट के आधार पर देखा जाये तो प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में 200 मीटर पर तालाब है तथा पश्चिम दिशा में 800 मीटर पर नदी है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में 230 मीटर पर आबादी, पूर्व दिशा में 80 मीटर पर कच्चा रोड़ है तथा लीज क्षेत्र का मध्य भाग खुदा हुआ है।

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

प्रकरण की विवेचना के दौरान पाया गया कि माइन प्लान के साथ जो मेप अपलोड किये गये वह पठनीय नहीं है अतः ई.आई.ए. के साथ पठनीय संपूर्ण माइन प्लान मय मेप के, लीज स्वीकृति आदेश तथा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
2. खदान के साथ प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 1759 दिनांक 23/11/2021 में यह उल्लेखित है कि प्रश्नाधीन खदान स्थल वन क्षेत्र क्रमांक 1236/753 की दूरी 165 मीटर है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-5/16/81/10-3, भोपाल दिनांक 07/10/02 की कण्डिका-छ में लेख है कि उक्त आदेश पूर्व में स्वीकृत खदानों में लागू नहीं होंगे । किंतु वर्तमान में प्रचलित आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि 2002 के पूर्व स्वीकृत खनिज रियायतों के ऐसे प्रकरण जिनकी वन क्षेत्र से दूरी 250 मीटर से कम है, में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक है या नहीं । अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक सम्पूर्ण विवरण औचित्य के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे ।
3. माइन प्लान के साथ जो मेप अपलोड किये गये वह पठनीय नहीं है अतः ई.आई.ए. के साथ पठनीय संपूर्ण माइन प्लान मय मेप के, लीज स्वीकृति आदेश तथा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये ।
4. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
5. लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं, अतः ट्री इन्वेट्री मय प्रजाति का नाम उनकी संख्या, ऊंचाई एवं कालर गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

7. Case No 9111/2022 Smt. Vishnukanta Anjana, Owner, Village - Ratikhedi, Dist. Mandsaur, MP - 458001, Prior Environment Clearance for Murrum & Stone Quarry in an area of 1.573 ha. (Stone - 18536 cum per annum, Murrum - 4119 cum per annum) (Khasra No. 369), Village - Digaonkhurd, Tehsil - Mandsaur, Dist. Mandsaur (MP)

This is case of Murrum & Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site ((Khasra No. 369), Village - Digaonkhurd, Tehsil - Mandsaur, Dist. Mandsaur (MP) 1.573 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा,

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत किये गये । प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2545 दिनांक 07/12/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत/संचालित है, जिसका कुल रकबा 03.093 है. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में 60 मीटर पर रोड है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा 40 मीटर का सेट-बैक छोड़ा गया है जो कि प्रस्तुतीकरण के सरफेस में दिखाया गया है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 430 मीटर पर आबादी है तथा पश्चिम दिशा में 280 मीटर पर एक शेड (गौशाला) है। अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण/सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 23/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 18536 मी³ प्रति वर्ष एवं मुरुम 4119 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 08.82 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.98 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.35 लाख :-

	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
1	गौशाला, स्कूल एवं आंगनबाड़ी में 170 वृक्ष ट्री गार्ड एवं नाम प्लेट के साथ प्रजाति - नीम,मौलश्री,कचनार,कदम, पुत्रन्जीवा,बरगद,पीपल	85,000
2	डीगाँवखुर्द गाँव के आंगनवाड़ी केंद्र में 1 वर्ष तक पोषण आहार वितरण	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :

वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा संख्या
----------------------------	---------------------	---------------

**566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022**

बैरियर जोन	नीम,सिस्सो, करंज,चिरोल, सीताफल,सफेद कैस्टर एवं अन्य प्रजातियाँ।	1630
नॉन माइनिंग जोन	कटंग बांस, नीम, करंज, सीताफल	400
परिवहन मार्ग 100 मी.	नीम,कटंग बांस,करंज,गुलमोहर,जंगल जलेबी।	200
विद्यालय, आंगनबाड़ी, गौशाला में	मौलश्री,पुत्रन्जीवा,कचनार,कदम, (विद्यालय,आंगनबाड़ी) मौलश्री,पुत्रन्जीवा,कचनार,कदम,नीम,बरगद,पीपल (गौशाला में)	170 विद्यालय, (100) आंगनबाड़ी, (50) गौशाला में (20)

8. Case No 9112/2022 Shri Shriniwas Kushwah, Ward No. 6, Shivpuri Road, Village - Dabipura, Post - Vijaypur, Dist. Sheopur, MP - 476332 Prior Environment Clearance for Soil Quarry in an area of 1.0 ha. (1200 cum per annum) (Khasra No. 1859, 1860/1), Village - Vijaypur, Tehsil - Vijaypur, Dist. Sheopur (MP)

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1859, 1860/1), Village - Vijaypur, Tehsil - Vijaypur, Dist. Sheopur (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 23/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत किये गये । प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2440 दिनांक 07/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में 40 मीटर पर रोड़ इसलिए 10 मीटर का सेटवेक, पश्चिम दिशा में 10 मीटर पर प्राकृतिक नाला है इसलिए 40 मीटर का सेटवेक तथा पूर्वी क्षेत्र में 90 मीटर पर नहर है इसलिए 10 मीटर का सेटवेक छोड़ा जाना होगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार पूर्व से ही सेटवेक प्रस्तावित किया गया है जो प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पी.पी. ने बताया कि ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है, 02 मीटर से अधिक उत्खनन नहीं किया जायेगा, कोई भी वृक्ष नहीं काटा जायेगा तथा चिमनी भी प्रस्तावित स्थल पर स्थापित नहीं की जावेगी । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि
 - लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ हैं, जिसे नहीं काटा जायेगा।
 - लीज क्षेत्र से चिमनी की स्थापना नहीं की जावेगी।
 - 02 मीटर गहराई तक ही उत्खनन किया जावेगा।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. योजना।
- ✓ खदान के दक्षिण दिशा में 40 मीटर पर रोड़ इसलिए 10 मीटर का सेटवेक, पश्चिम दिशा में 10 मीटर पर प्राकृतिक नाला है इसलिए 40 मीटर का सेटवेक तथा पूर्वी क्षेत्र में 90 मीटर पर नहर है इसलिए 10 मीटर का सेटवेक दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 23/4/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्वाइल – 12,00 मी.3 प्रति वर्ष।
2. 02 मीटर से अधिक गहराई का उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.36 लाख प्रति वर्ष।
4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम प्रहलादपुरा तहसील विजयपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में फर्नीचर (बीस लकड़ी की बेंच और दस लकड़ी की कुर्सीयाँ) एवं चबुतरों का प्लास्टर	50,000
योग	50,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित स्थान	लगाए जाने वाले पौधों के प्रकार	मात्रा
परिवहन मार्ग	कदम्ब, नीम, कचनार, कुम्भी, जामुन करंज, आंवला, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	50
बैरियर जोन	आंवला, सिस्सू, नीम, पीपल, करंज, जामुन खमेर, चिरोल, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	600

**566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022**

नॉन माइनिंग जोन	आम अमरुद ऑवला शीशम कटहल मुनगा नीम जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	350
ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, सीताफल, आवंला, जामुन नीबू आम, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	200
कुल योग		1200

9. Case No 9095/2022 M/s Shahid Stone Crusher, Prop. Shri Shahid Ali, Ward No. 03, Kotma, Tehsil - Kotma, Dist. Annupur, MP - 484336, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.004 ha. (6002 cum per annum) (Khasra No. 52/568, 52/569), Village - Baskhala, Tehsil - Kotma, Dist. Anuppur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 52/568, 52/569), Village - Baskhala, Tehsil - Kotma, Dist. Anuppur (MP) 1.004 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति 564वीं बैठक की दिनांक 15/04/22 में प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

आज दिनांक 23/04/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत किये गये। प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 532 दिनांक 29/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत/संचालित है, जिसका कुल रकबा 2.884 है. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 145 मीटर पर कच्चा रोड है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 390 मीटर पर जलाशय है। आवंटित क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 500 मीटर पर आबादी है एवं लीज क्षेत्र में 35 पेड़ जो की नीम, सलाई, पलाश, शीशम, प्रजाति के हैं जिनमें से 07 पेड़ स्वीकृत क्षेत्र के 7.5

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

मीटर बेरीअर जोन क्षेत्र में है जिन्हें उखाड़ा नहीं जाएगा एवं 28 पेड़ खदान के खनन योग्य क्षेत्र में है, जिनमें से 07 पेड़ों को अनुमति मिलने के उपरांत उखाड़ा दिया जावेगा एवं प्रत्येक उखाड़े गये पेड़ के एवज में 10 गुना उन्ही प्रजातियों के 70 अतिरिक्त पेड़ रोपित किए जावेंगे । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ लीज क्षेत्र में काटे जाने वाले 07 पेड़ों की इन्वेंट्री तथा अतिरिक्त वृक्षारोपण का वचन पत्र ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 23/04/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 6,002 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.85 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.53 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख :-

सी. ई. आर. गतिविधि		
साल	गतिविधि	कुल दर (रु में)
1	250 फल देने वाले पौधे (50/-) (आंवला, आम, मुंनगा, कटहल, इमली, अमरुद, पपीता, नींबू, हर्षा, बहेड़ा, जामुन) ग्राम बसखाला में एक वर्ष में वितरित किए जाएंगे। (यह गतिविधि मध्य प्रदेश सरकार की “अंकुर योजना” के तहत की जाएगी।	12,500
2	ग्राम बसखाला के शासकीय विधालय में बच्चों के मध्यान भोजन के लिए पूरक पोषण आहार का वितरण किया जाएगा।	37,500
योग		50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1500 वृक्षों का वृक्षारोपण :

**566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022**

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन एवं गैर खनन क्षेत्र	नीम, पीपल, शीशम, बरगद, आम, इमली, चिरोल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ एवं प्रत्येक चार पौधों के बीच में एक सीताफल का पौधा लगाया जावेगा । गड्डे का आकार 60×60 से.मी. बेरीअर जोन का कुल क्षेत्र – 3090 वर्ग मीटर गैर खनन क्षेत्र का कुल क्षेत्र – 2000 वर्ग मीटर	1200
2	परिवहन मार्ग	नीम, करंज, आम, शीशम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ । गड्डे का आकार 70×70 से.मी.	50
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरुद, पपीता, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	250
योग			1500

10. Case No 9099/2022 Shri Rajesh Bahadur Singh, Leesees 141, Ghuman, Neem Ke Paas, Ghuman Kalan, Dist. Rewa, MP - 486556, Prior Environment Clearance for Stone Gitti Quarry in an area of 1.80 ha. (15876 cum per annum) (Khasra No. 1042/4), Village - Ghuman Kalan, Tehsil - Jawa, Dist. Rewa (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1042/4), Village - Ghuman Kalan, Tehsil - Jawa, Dist. Rewa (MP) 1.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 566वीं दिनांक 23/04/22 एवं समिति की पूर्व की 564वीं बैठक दिनांक 15/04/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है ।

**566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022**

Discussion on query replies submitted by PP or file received from SEIAA

11. Case No 7322/2020 Smt. Manju Singh W/o Shri Narendra Bahadur Singh, R/o Bamhangawan, Tehsil - Raghurajnagar, Dist. Satna Prior Environment Clearance for Laterite Quarry in an area of 5.70 ha. (18530 cum per annum) (Khasra No. 2P), Village - Bihra, Tehsil - Kotar, Dist. Satna (MP) EIA Con.

This is case of Laterite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2P), Village - Bihra, Tehsil - Kotar, Dist. Satna (MP) 5.70 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 448वीं दिनांक 23/07/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

प्रकरण समिति की 563वीं बैठक दिनांक 04/04/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

समिति की बैठक दिनांक 15/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आनंद गुप्ता उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लेटराइट खदान होने के कारण उत्खनन के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण-पश्चिम दिशा से 120 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ तथा दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण दिशा की तरफ लगभग 110 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट है । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि खदान के मध्य भाग से कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः कच्चे रोड़ के दोनों ओर 20-20 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना चाहिए तथा परियोजना प्रस्तावक को पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह भी पाया कि खदान के पश्चिमी भाग में कुछ पेड़ (35) लगे हैं । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको काटा जाना प्रस्तावित नहीं है, यह क्षेत्र नॉन माईनिंग जोन में छोड़ा जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसे: मंदिर हेतु सीढ़ी का निर्माण, तहसील भवन/विद्यालय की मरम्मत, गौशाला का विकास कार्य, पेयजल की व्यवस्था एवं सोलर लाईट) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

- ✓ खदान के पश्चिमी भाग में कुछ पेड़ (35) लगे हैं, अतः ट्री इवेंट्री (मोटाई, गोलाई, ऊँचाई एवं प्रजाति) ।
- ✓ पुनरीक्षित सरफेस प्लॉन, जिसमें नॉन माईनिंग जोन दिखाते हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन प्रस्तुत की गई जिस कारण उसे एजेण्डा में सूचीबद्ध किया गया ।

आज दिनांक 23/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आनंद गुप्ता उपस्थित हुए तथा क्वेरी प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाया गया । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के पश्चिमी भाग में पेड़ 35 लगे हैं जिनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जायेगा तथा जिस भाग में पेड़ लगे हैं, उसे नॉन माईनिंग जोन छोड़ा गया है । इसी प्रकार खदान के पूर्वी भाग की ओर जहाँ से कच्चा रोड़ निकल रहा है के दोनों तरफ 20-20 मीटर का सेट-बैक छोड़ा गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार 5.70 हे. एरिया में से नॉन माईनिंग जोन छोड़ने के बाद खनन हेतु 4.06 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता लेटराइट – 18,530 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 36.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.57 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.16 लाख :-

क्र.सं	गतिविधियां	प्रदेय	आवर्ती व्यय रु.
1.	बुनियादी ढांचे का विकास		
a.	ग्राम बिहरा में विद्यालय की मरम्मत/नवीनीकरण।	1 विद्यालय	31,000.00
b.	गौशाला के विकास एवं रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता।		50,000.00
c.	प्रस्तावक आंगनबाड़ी केन्द्र बिहरा को बच्चों के कल्याण कार्यक्रम "पोषण आहार" के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।		50,000.00
d.	गांव में सोलर लाइट की स्थापना	लाइट सोलर 1	25,000.00
2.	स्वास्थ्य		
a.	ग्राम बिहरा में कोविड महामारी में आवश्यक एहतियात के लिए ग्रामीणों को सैनिटाइजेशन किट (हैंड सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स एवं मास्क) का वितरण एवं प्रशिक्षण। (100 व्यक्ति ; @ 300/सेट)		30,000.00

**566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022**

c.	ग्राम बिहरा में विद्यालय में शौचालय का निर्माण।		30,000.00
कुल			2,16,000.00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	पौधों की संख्या
बैरियर जोन	सिरिस, बरगदा, लसोड़ा, सहतूत, अंजन, शीषम, तिनसा, कचनार, नीम, कुसुम, बारगा, गधापलाष, कुम्भी तथा अन्य स्थानीय प्रजातियां/	2000
	जंगलजलेबी, चिरोल, खमेर, करंज, नीम, हरश्रृंगार के साथ सिस्वेनिया एवं सू-बबूल की सीड सोइंग।	360
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	सिरिस, बरगदा, लसोड़ा, सहतूत, अंजन, शीषम, तिनसा, कचनार, नीम, कुसुम, बारगा, गधापलाष, कुम्भी तथा अन्य स्थानीय प्रजातियां/	1000
	जंगलजलेबी, चिरोल, खमेर, करंज, नीम, हरश्रृंगार के साथ सिस्वेनिया एवं सू-बबूल की सीड सोइंग।	440
खनन क्षेत्र के आसपास के गांवों (बिहरा, निम्हा, देवरा) में ग्रामवासियों को पौधे वितरित किए जाएंगे	नीम, महुआ, नींबू, कटहल, गुग्गल/	950
विद्यालय के पास वृक्षारोपण	अशोक, नीम, कुसुम, सिशम, सीताफल, कदम कचनार, पाकड़	50
कुल		4800

12. Case No 8730/2021 M/s Sunny Paint & Tar Products, 12-A, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Dist. Indore, MP Prior Environment Clearance for "Expansion of Paint & Varnishes Manufacturing Plant" at A/72, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore (MP). Env. Cons:- M/s. Gurung Environment Solutions Pvt. Ltd. Jaipur, Raj.

This is a case of Prior Environment Clearance for "Expansion of Paint & Varnishes Manufacturing Plant" at A/72, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore (MP) Cat. 5(f) Synthetic organic chemicals industry. The proposed project falls under item

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

no 5(f) i.e. Synthetic organic chemicals hence requires prior EC from SEIAA before initiation of activity at site.

The case was presented by the PP Shri Sunny Dhamija and their Env. Consultant M/s. Mr. Kapil Singh M/s. Gurung Environment Solutions Pvt. Ltd. Jaipur in the SEAC 489th meeting dated 12.03.2021, wherein PP stated following salient features and other details of the project .

M/s. Sunny Paint & Tar Products (An ISO Certified Company) was established in the year of 1989. Company is leading Manufacturer of an extensive array of, Oil Alkyds Resins, Thermosetting Acrylic Resins, Amino Resins, Rosin Derivatives, Polyamide Resin, Amino Resins, etc. Sunny Paint have a sound infrastructure, which helps in the smooth and systematic execution of all production related tasks. It is equipped with advanced machinery and cutting-edge technology that ensures swift rate of production. Plant has a state-of-the-art infrastructure that is fully equipped with the world class amenities providing with a resourceful environment. One of the units of Sunny Paint is in Indore, MP. Indore unit is located at A/72, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore, Madhya Pradesh-452001 in an area of 1394 sqm. It is an operational unit engaged in Manufacturing of different kind of Paint, Tar and Varnishes. The unit is only for formulation. Unit has valid consent to operate issued by MPPCB vide Consent no. AWH86616 valid upto 31.12.2021. Being a formulation unit, environmental clearance is not applicable to the existing unit.

The project of M/s Sunny Paint & Tar Products located in Plot No. A/72, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore, Madhya Pradesh- 452001 for manufacturing of 10,000 MT of synthetic resin (Alkyd Resin & Maleic/Phenolic Resin) with existing formulation unit. The unit configuration and capacity of existing project is given as below

Sl.N o.	Name	Existing Units		Proposed Units		Total (Existing +Proposed)	
		Configurati on	Production (TPA)_	Configu ration	Production (TPA)	Configuration	Production (TPA)
1	Bitumen Primer	-	105	-	0	-	105
2	Ceiling Compound	-	105	-	0	-	105
3	Distemper Dry and Oil Bound	-	60	-	0	-	60
4	Enamel Road Marking, Black	-	30	-	2970	-	3000

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

	Japan, Red Oxide						
5	Expansion Joint Filler Board	-	3000	-	0	-	3000
6	French Polish	-	6	-	0	-	6
7	Tarfelt	-	24000 nos.	-	0	-	24000
8	Varnish Terfaintine	-	12	-	0	-	12
9	Resin	-	0	-	10000	-	10000

The details of the raw material requirement for the proposed project/ expansion cum proposed project along with its source and mode of transportation is given as below:

Sr. No.	Name of Raw Materials	Quantity (MT/MT)
1	<i>Alkyd Resin</i>	
1	Rosin Oil	0.4
2	Pentaerythritol	0.084
3	Glycerine	0.079
4	Phthalic Anhydride	0.205
5	Maleic Anhydride	0.018
6	Benzoic acid	0.011
7	Caustic Soda	0.001
8	Triphenyl Phosphate	0.001
9	Hypo Phosphorous Acid	0.001
10	Xylene	0.02
11	MTO	0.22
2	<i>Maleic/Phenolic Resin</i>	
1	Rosin	0.833
2	Pentaerythritol	0.05
3	Glycerine	0.056
4	Bisphenol	0.056
5	Paraformaldehyde	0.039
6	Triphenyl Phosphate	0.001
7	Maleic Anhydride/Phenol	0.077

The water requirement for the project after expansion is estimated as 12 KLD, out of which 12 KLD of freshwater requirement will be obtained from the private tankers.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

- The power requirement for the project is estimated as 125 HP MW which will be obtained from Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPPKVVCL).
- The cost of the project is Rs 1.54 Crores. The employment generation from the project is 60 no.
- Summary of violation under EIA, 2006/court case/show cause/direction if any, related to the project under consideration shall be furnished - Not Applicable
- Name of the EIA consultant: M/s Gaurang Environmental Solutions Pvt. Ltd. [S.No. 111; List of ACOs with their Certificate No. NABET/EIA/2023/RA0192 (Valid till 19.01.2023).

During presentation PP submitted that they are seeking EC for Resin and their other products are non EC products. After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with along with following additional TORs as annexed in annexure-D:

1. Justify the expansion wrt to plant area of 1394 SQM and existing and proposed facility to be depicted on layout map on suitable scale.
2. Plant layout with legible labeling of each facility and area should be provided on A3 size paper.
3. Explore the possibility of getting water supply through IMC in place of water tankers.
4. Compliance of CTO duly authenticated by Regional Officer, MP Pollution Control Board.
5. Explore the possibility of clean fuel for boiler, discuss if any additional boiler is required.
6. Current status of HW and Fly ash management & disposal plan is to be submitted in the EIA report
7. MSDS of all chemicals (reactants, products and intermediates) should be provided with the EIA report.
8. Current status and disposal of HW & fly ash management plan is to be submitted in the EIA report.
9. Submit mass balance with chemical commercial and common names.
10. Percentage of Solvent recovery if any.
11. PP should explore possibility of using Bio-fuel based technology in boilers.
12. Chemical storage plan as per their compatibility and storage area containment plan shall be discussed in the EIA report.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in in the SEAC 489th meeting dated 12.03.2021, wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by the PP Shri Sunny Dhamija and their Env. Consultant M/s. Mr. Kapil Singh M/s. Gurung Environment Solutions Pvt. Ltd. Jaipur before the committee; during discussion following details of this project was submitted by the PP:

- The proposal is for Environmental Clearance for “Expansion of Paint & Varnishes Manufacturing Plant” located at A/72, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore, Madhya Pradesh-452001 by M/s M/s Sunny Paint & Tar Products.
- The industry is involved in manufacturing of the several products like Bitumen Primer, Ceiling Compound, Distemper Dry and Oil Bound, Enamel Road Marking, Black Japan, Red Oxide, Expansion Joint Filler Board, French Polish, Tareelt, Varnish Turpentine. The unit is operational in accordance with Consent to Operate granted by Madhya Pradesh Pollution Control Board vide Consent No. AWH-86616 dated 28.03.2021 (valid upto 31.12.2024).
- Now, company has proposed to manufacture 10,000 MT of Synthetic Resin (Alkyd Resin & Maleic/Phenolic Resin) along with the enhancement of few of the existing products in the existing plant.
- Unit is spread over an area of 1394 Sqm. The proposed expansion shall be done within the existing premises.
- Project being a Small scale Industry located in industrial area, it is exempted from Public Hearing.
- Freshwater requirement of the project after expansion will be 12 KLD sourced from private tankers. The wastewater generation from the industrial process will be 2 KLD which will be sent to the CETP for treatment and final disposal. The domestic wastewater generation will be 2.5 KLD which will be disposed into septic tanks via soak pit.
- The power requirement for the proposed expansion will be 125 HP will be supplied through M.P. Paschim Kshetra Vidhyut Vitaran Company Limited, Indore. Existing DG Set of 125 kVA will be used in the plant during emergency failure.
- The source of air pollution from existing and proposed expansion is mentioned below:

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

S. No.	Stack Attached	Capacity	Fuel Used	Stack Height	APCM	Expected Pollutants
Existing						
1	Boiler	6 Lac K Calories/hr	Bio Briquette	30	Bag Filter, Dust Collector and Natural Draft	PM, Sox, NOx
2	DG Set	125 KVA	HSD	11	Stack & Natural Draft	PM, Sox, NOx

During presentation, PP submitted that they are seeking EC for Resin and Enamel Road Marking, Black Japan, Red Oxide being these are EC products and rest are non EC products. After detail discussion committee has asked the PP to submit the following information:

1. Commitment from the PP that 96% solvent recovery will be achieved.
2. Revised EMP and CSR as suggested by the committee during presentation.
3. Revised Plantation Scheme along with its species and total area coverage for plantation should be atleast 33% around and along the periphery of plot.
4. Justification for Tarfelt quantity with size.
5. Details of plantation done till date & what was planted as condition of plantation is not compiled as per consent condition.
6. Revised Mass balance as suggested by the committee.
7. Mass balance & chemical reaction for Enamel Road Marking, Black Japan, Red Oxide.
8. Correct chemical reaction w.r.t. alkayd resin.
9. Legible Lay pout plan.
10. Quantify carbon foot print after the expansion of products.

The case was presented by the PP and their applicant in the 565th SEAC meeting dated 16-04-22, wherein it was observed by the committee that the submitted mass balance still needs correction. Thus after presentation, PP was asked to submit revised mass balance with chemical reactions of all EC products as suggested by committee for further consideration.

PP vide their letter dated 19/04/2022 uploaded online query reply well on “Parivesh Portal”. Wherein PP submitted following reply wrt query raised in the SEAC 565th SEAC meeting dated 16-04-22. PP submitted that proposed project includes manufacturing of Resin and capacity enhancement of Enamel Road Marking, Black Japan, Red Oxide product. Resin being a synthetic organic product, it attracts the

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

purview of Environmental clearance. However, other product doesn't attract Environmental Clearance as those are formulation products. Thus, we are attaching Mass Balance, manufacturing process and chemical reactions of Resin.

The all query reply submitted by PP which was placed before the committee and the same found satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for "Expansion of Paint & Varnishes Manufacutring Plant" at A/72, Sector-C, Industrial Area, Sanwer Road, Indore (MP). Cat. - 5(f), subject to the following special conditions:

The EC shall be valid for following products and given capacity:

S. No.	Product	Unit	Existing (Quantity)	Proposed (Quantity)	After Expansion (Quantity)
Existing (Non- EC product)					
1.	Bitumen Primer	MTPA	105	0	105
2.	Ceiling Compound	MTPA	105	0	105
3.	Distemper Dry and Oil Bound	MTPA	60	0	60
4.	Enamel Road Marking, Black Japan, Red Oxide	MTPA	30	2970	3000
5.	Expansion Joint Filler Board	MTPA	3000	0	3000
6.	French Polish	MTPA	6	0	6
7.	Tareelt	Nos/Year	24000	0	24000
8.	Varnish Terfaintine	MTPA	12	0	12
New Products (EC Products)					
9.	Resin	MTPA	0	10000	10000

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

(A) Statutory compliance:

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
2. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. The gaseous emissions from the boiler, one DG sets (1 x 125 kVA) and scrubber shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines:
3. Storage of raw materials, chemicals etc shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
4. The one DG sets (1 x 125 kVA) shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
5. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
6. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

2. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
3. Total fresh water requirement shall not exceed 12.0 KLD (out of which 3 KLD for domestic, 08 KLD for industrial water use & 01KLD for green belt use purpose) .
4. Total wastewater generation after expansion will be 4.5 KLD (Domestic: 2.5 KLD & Industrial: 2 KLD). 2.5 KLD domestic sewage will be disposed to septic tank followed by soak pit. Around 2.0 KLD wastewater is expected to be generated as industrial effluent which will be sent to the CETP for treatment after pre-treatment at site.
5. In case, if in-house bore or tube well is required, than CGWA permission shall be obtained before extracting ground water.
6. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
7. The Company shall harvest rainwater, after taking permission from State Pollution Control Board, from the roof tops of the admin buildings. Process building, raw material and finished goods storage building shall not be used for ground water recharging.
8. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets (1 x 125 kVA) for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

2. The existing power requirement of project is 75 HP and will be increased to 125 HP after expansion. Electricity is being sourced by M.P. Paschim Kshetra Vidhyut Vitaran Company Limited.

(F) Waste management

1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
2. Hazardous waste such as Used oil, Discarded containers/drums, shall be handled & disposed as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 as follows:

Sr. No	Name of Waste	Source of Generation	Category No. (As per Sch-I&II 2016)	Quantity (After Expansion)	Mode of Treatment & Disposal Method
1	Discarded Containers/ Bags /Liners	Storage & Handling of Raw Materials	Sch-I/33.3	5000 Nos/year	Collection, Storage, Decontamination or sale to authorised decontamination facility
2	Used/Spent Oil	Used/Spent Oil	Sch-I/5.1	0.1 KL/year	Collection, Storage, Transportation & Disposal by selling to registered Refiners.
3	Wastewater treatment sludge	-	Sch-I/34.3	2 MT/year	Collection, Storage, Transportation and disposal to authorized TSDF.
4	Fly Ash	Boiler	Non-Haz	0.1 TPD	Sent to brick manufacturer
5	Municipal Waste	-	Municipal Waste	18 Kg/day	Disposal at approved municipal site.

3. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
4. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate fire fighting systems should be provided for the storage area.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

5. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
6. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
7. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
8. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.
9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
10. Proper fire fighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
12. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
13. ETP sludge, process inorganic salt shall be disposed off to the TSDF.

(G) Green Belt

1. The PP will develop greenbelt of 512 sqm (36.73 % of total plot area) in the plant. A wide green belt will be developed around the plant boundary. Around 120 trees shall be planted within the premises.
2. Also 3000 plants shall be planted, maintained and protected for minimum 05 yeras on Kshipra River through forest department, Ujjain.
3. The green belt of 5-10 m width shall be developed near the total project area, mainly along the plant periphery, in downward wind direction and along road sides etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the Forest Department.

4. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 1-1.5 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature.
5. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Fire fighting system shall be as per the norms.
3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) EMP & CER

1. The proposed EMP cost is Rs. 23.50 lakhs and 02.50 lakhs/year as recurring cost and out of which the Environment Monitoring Cost for the project is 1.0 lakhs and Rs. 0.40 lakhs is proposed for green belt development.
2. Under CER activity, PP has proposed Rs. 02.00 lakhs proposed for following different activities.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

S.No.	Activities	Contribution (Rs. In Lakhs)		
		1 st Year	2 nd Year	3 rd Year
1.	Installation of Solar Panels in nearby School	24000	20000	20000
2.	Provision of Health Awareness Camps	14000	14000	14000
3.	Vaccination Drives	24000	20000	20000
4.	Cattle Health Checkup in nearby villages	10000	10000	10000
Sub-total		72000	64000	64000
TOTAL		Rs. 2,00,000		

3. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
4. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
5. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
6. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
7. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly

**566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022**

approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

8. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

13. Case No 9069/2022 M/s Navratanamal Gugalia & Sons Madanpura Laterite & Fireclay Mine, Shri Sharad Chandra Gugalia, Leasee, Industrial Area, Katay Ghat Road, Dist. Katni, MP - 483501 Prior Environment Clearance for Laterite & Fireclay Mine in an area of 1.80 ha. (20848 Tonne per annum) (Khasra No. 294, 296/2, 298/1, 299), Village - Madanpura, Tehsil - Murwara, Dist. Katni (MP)

This is case of Laterite & Fireclay Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 294, 296/2, 298/1, 299), Village -

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

Madanpura, Tehsil - Murwara, Dist. Katni (MP) 1.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

समिति 561वीं बैठक दिनांक 21/03/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन लाईन उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 439 दिनांक 09/3/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, किंतु संलग्नक ऑन लाईन अपलोड नहीं है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि त्रुटिवश यह प्रमाण पत्र अपलोड होना रह गया है तथा वे इसकी फोटोकाफी लाये हैं । फोटोप्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) प्रमाण-पत्र क्रमांक 5733 दिनांक 08/12/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि के अंदर कोई अन्य खदान स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है । प्रकरण की परीक्षण के दौरान पाया गया कि वन मण्डलाधिकारी, कटनी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 13/11/15 द्वारा आवेदित क्षेत्र के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 79 स्थित होने से आपत्ति व्यक्त की गई थी । तत्संबंध में स्वीकृत खनिजपट्टा क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर के अंदर होने के कारण निराकरण हेतु प्रकरण संभागायुक्त की समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रेषित किया गया था । संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 28/11/20 अनुसार वन सीमा की ओर चेनलिंग, फेन्सिंग एवं स्पष्ट मुनारे लगाये जाने की शर्त पर अनुशंसा की गई है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन लेटराइट एवं फायवले का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 360 मीटर पर रेलवे लाईन हैं । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज उत्खनन के दौरान आवंटित क्षेत्र में कोई पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव नहीं है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ खसरा मेप को गूगल इमेज पर सुपरइम्पोज कर प्रस्तुत किया जाये, ताकि खनन क्षेत्र की वन सीमा से दूरी ज्ञात हो सके तथा लीज क्षेत्र के अंदर से 30 मीटर का सेट-बैक (नॉन माइनिंग क्षेत्र) छोड़ने का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाये ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र क्रमांक 5733 दिनांक 08/12/21 की फोटोप्रति ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 21/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता लेटराईट एवं फायरक्ले – 20,848 टन प्रति वर्ष।
2. वन क्षेत्र की ओर से लीज के अंदर से 30 मीटर का सेट-बैक (नॉन माइनिंग क्षेत्र) छोड़ा जाये।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 82,000 लाख प्रति वर्ष।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख :-

सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
रोड मरम्मत	50,000
ग्राम मदनपुरा में खेल सामग्री वितरण	20,000
ग्राम मदनपुरा में फलदार पौधों का वितरण 600 नग	30,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र०	प्रस्तावित वृक्षारोपण	पौधों की प्रजातियां	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन गारलैंड नाली	नीम, गुलमोहर, बांस, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
2.	परिवहन मार्ग के किनारे (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, करंज, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
3.	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, इमली, नीम, कटहल, नींबू, अमरुद, जामुन, करोदा, मुनगा एवं अन्य आवश्यकतानुसार।	600
कुल			2000

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 716वीं बैठक दिनांक 07/4/2 में सेक की 561वीं बैठक दिनांक 21/3/2 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रस्तावित स्थल की पूर्व से खुदाई होना परिलक्षित है एवं अन्य खदान भी दिख रही है जबकि खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन में स्पष्ट नहीं है, के आधार पर इस प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण कर अनुशंसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के प्रकाश में प्रकरण आनलाईन सेक को प्रेषित किया गया।

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

इस प्रकरण को आज दिनांक 23/04/22 को सूचीबद्ध कर समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परीक्षण में पाया गया कि :-

- इस प्रकरण में लीज मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा दिनांक 28/02/2003 को स्वीकृत की गई थी जो 2023 तक वैध है तथा इसका माइन प्लान दिनांक 09/05/21 को स्वीकृत हुआ ।
- कृपया अनुमोदित माइन प्लान के पेज क्रमांक-18, 22 एवं 24 का अवलोकन हो, जिनपर स्पष्ट उल्लेख है कि लीज क्षेत्र में 02 पुरानी पिट (पिट-ए 30X15 X02 मीटर पिट-बी 145 X 100 X 3.14 मीटर) हैं तथा यह दोनों ही पिट अनुमोदित सरफेस मेप पर भी दिखाई गई है । इसी प्रकार अनुमोदित खनन योजना में दिए गए लेण्ड यूज में भी यह स्पष्ट किया गया है कि 1.49 हेक्टेयर एरिया खुदा हुआ है जो प्रस्तुतीकरण के दौरान दिए गए पी.पी.टी. में उल्लेखित है ।
- गूगल इमेज की पुरानी इमेज के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि लीज क्षेत्र में विद्यमान उपरोक्त दोनों पिट 2013 से दृष्टिगत है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि लीज क्षेत्र में पूर्व से 02 पिट विद्यमान हैं जो 2013 के पूर्व की हैं जिनका विवरण अनुमोदित माइन प्लान व सरफेस मेप में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिखाया गया है । समिति ने कलेक्टर, (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र क्रमांक 5733 दिनांक 08/12/21 के अनुसार अपनी अनुशंसायें प्रेषित की हैं, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि -

“उपरोक्त विषयांतर्गत मेसर्स नवरत्नमल गुगालिया एण्ड संस, इण्डस्ट्रीयल एरिया कटनी के पक्ष में ग्राम मदनपुरा, तहसील कटनी के खसरा नं. 294, 296/2, 298/1, 299 कुल रकबा 1.80 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज लेटराईट, फायरक्ले का खनिपट्टा 20 वर्ष की अवधि दिनांक 23/7/03 से 22/7/23 तक के लिए अनुबंधित है ।

आवेदक द्वारा उक्त क्षेत्र से 500 मीटर के परिधि में आने वाले अन्य खनि रियायतों के संबंध में जानकारी प्रदाय किये जाने का अनुरोध किया गया है । कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उक्त स्वीकृत खनि रियायत क्षेत्र से 500 मीटर के परिधि के अंदर कोई अन्य खनि रियायत स्वीकृत नहीं होना पाया जाता है । वांछित जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।”

समिति द्वारा प्रकरणों के परीक्षण के दौरान इन सभी कारकों का पूर्ण ध्यान रखा जाता है तथा यदि स्वीकृत खदान के आसपास कोई पूर्व की उत्खनन गतिविधियाँ ध्यान में आती हैं तो गूगल इमेज से उनकी पूर्व की अवधि का आंकलन कर निर्णय लिया जाता है तथा गूगल इमेज से स्थिति स्पष्ट न होने पर ही पुनः खनिज अधिकारी इत्यादि से प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव दिया जाता है । कृपया मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक 108 दिनांक 31/1/22 की कण्डिका-6 का अवलोकन करें जिसमें यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि “वन विभाग एवं अन्य विभागों से लिखित एन.ओ.सी. प्राप्त करने के स्थान पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जहाँ तक संभव हो, तकनीकी/गूगल मेप का उपयोग कर निर्णय लिया जाये” ।

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

इस प्रकरण में भी समिति पुनः गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के चारों ओर की स्थिति का अवलोकन कर समिति अपनी पूर्व में 561वीं दिनांक 21/03/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लेती है ।

14. Case No 9074/2022 RAGHURAJ SINGH village Sarsaini Tehsil Jaura District Morena,,Morena,Madhya Pradesh-476001 Prior Environment Clearance for Stone (Gitty) Quarry in an area of 1.61 ha. (25000 Tonne per annum) (Khasra No. 34), village Bidhniya Tehsil Datia District Datia, Madhya Pradesh-475661

This is case of Stone (Gitty) Quarry . The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 34), village Bidhniya Tehsil Datia District Datia (M.P.) 1.61 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 561वीं बैठक दिनांक 21/03/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

समिति की 562वीं बैठक दिनांक 29/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 79 दिनांक 31/01/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत खदानों का एवं प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 3.61 हेक्टेयर है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 70 मीटर पर रोड हैं तथा पूर्व दिशा में 290 मीटर पर कच्चा रोड़ है । इसी प्रकार आर्वटित क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम दिशा में 75 मीटर पर तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर नहर है एवं लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 08

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

पेड़ काटे जावेंगे तथा उनके एवज में 80 पेड़ अतिरिक्त लगायेंगे । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- ✓ लीज क्षेत्र के उत्तर पश्चिम 75 मीटर नहर है, अतः 25 मीटर का सेट-बैक (नॉन माइनिंग जोन) दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेंप ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 29/03/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 घनमीटर प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.22 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.36
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.05 लाख :-

सी. ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
ग्राम बिड़निया में पीने के पानी के लिए बोरवैल खुदवाकर लिफ्टिंग पम्प लगाया जायेगा और उसे ओवरहेड टैंक में पाइपलाइन से जोड़ा जायेगा।	1,05,000
योग	1,05,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित स्थान	लगाए जाने वाले पौधों के प्रकार	मात्रा
बैरियर जोन	नीम, सीताफल, खमार, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सो आदि।	530
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, अशोक आदि	220

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1250
कुल योग		2,000

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 716वीं बैठक दिनांक 07/4/22 में सेक की 562वीं बैठक दिनांक 29/3/22 में की गई अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 70 मीटर पर रोड हैं तथा पूर्व दिशा में 290 मीटर पर कच्चा रोड है। इसी प्रकार आवंटित क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम दिशा में 75 मीटर पर तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में 230 मीटर पर नहर होना बताया गया है। चूंकि माननीय एन.जी.टी. के ओ.ए. नं. 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश दिनांक 09/7/20 के परिपालन में मानव बसाहट/संवेदनशील क्षेत्र/राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/पब्लिक रोड़/पुल/बांध/नदी/नहर इत्यादि में प्रस्तावित खन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिक खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित की गई है। उक्त आदेश/निर्देशों के परिपालन में पब्लिक रोड़ एवं नहर से प्रतिबंधित दूरी के दृष्टिगत खनन योग्य क्षेत्र की न्यूनतम उपलब्धता के दृष्टिगत पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रकरण को आज दिनांक 23/04/22 को सूचीबद्ध कर समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परीक्षण में पाया गया कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा ओ.ए. नं. 304/2019 में दिए गए निर्णय का अवलोकन हो, जिसमें यह उल्लेखित किया है कि जिन प्रकरणों में ब्लास्टिंग की जानी है उनमें 200 मीटर की दूरी तथा जिनमें ब्लास्टिंग नहीं की जानी है उनमें 100 मीटर की दूरी "Residential/Public buildings, Inhabited sites, locations to be considered by States" से प्रतिबंधित की गई है।

कृपया अवगत हो कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा ओ.ए. नं. 304/2019 में दिए गए निर्णय अनुसार "Residential / Public buildings, Inhabited sites" के अतिरिक्त अन्य locations राज्य द्वारा निर्धारित की जानी है तथा यह आदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समितियों द्वारा लागू किया जाना है। दिनांक 15/2/22 को SEIAA द्वारा SEIAA एवम् SEAC की आयोजित संयुक्त बैठक में भी इस पर विस्तृत चर्चा की गई थी जिसमें एसईआईए को अवगत कराया गया था कि क्योंकि सभी खदानें मध्यप्रदेश राज्य के एमएमआर, 1986 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप स्वीकृत की गई है, अतः खदान की प्रतिबंधित दूरी मध्यप्रदेश राज्य के एमएमआर, 1996 में

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 23 अप्रैल 2022

उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार लागू की जावे एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण क्रमांक 304/2019 में जारी आदेश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं निर्देश जारी करने बावत् प्रकरण राज्य शासन के माध्यम से संबंधित खनिज विभाग को भेजे जाने का अनुरोध किया गया था। उपरोक्त जानकारी एसईएसी की 549वीं बैठक दिनांक 15/02/22 के माध्यम से भी सिया को प्रेषित की गई थी। समिति ने पाया गया कि उनके द्वारा 562वीं बैठक दिनांक 29/3/22 माननीय एन.जी.टी. के ओ.ए. नं. 304/2019 में पारित आदेश के अनुरूप ही इस प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंसा की थी। अतः समिति की अनुशंसा है कि माननीय एन.जी.टी. (ओ.ए. नं. 304/2019) में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार “Residential/Public buildings, Inhabited sites के अतिरिक्त अन्य लोकेशनस के संबंध से 100 मीटर अथवा 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित करने बावत् प्रकरण राज्य शासन व खनिज विभाग को विस्तृत निर्देश जारी करने हेतु भेजा जाये।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

- b. Mining Lease area of the project (in ha.)
- c. Production capacity of the project.
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

566वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2022

- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

- नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.